@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ विश्वासघात किया है'

वर्ष-16, अंक-04 16-28 फरवरी, 2021 (पाक्षिक) ₹20

बजट के छह स्तंभ

- स्वास्थ्य और कल्याण
- वास्तविक एवं वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा
- आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
- नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

'आत्मनिर्भर भारत' को गति देने वाला बजट

मालदा (पश्चिम बंगाल) के शाहपुर गांव में तीन हजार किसानों के साथ राज्यव्यापी 'कृषक सुरक्षा सह-भोज' में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

पुडुचेरी में एक विशाल रैली के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

त्रिशूर (केरल) में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते केरल भाजपा नेतागण

मदुरै (तमिलनाडु) में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) में एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और साथ में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस व अन्य

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 बजट में किसानों की आय में वृद्धि, युवाओं के लिए अवसर और मजबूत अवसंरचना पर जोर

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नये दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर...

25 मन की बात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जनवरी को कहा कि कोरोना महामारी का सालभर मजबूती से मुकाबला करने के बाद भारत आज दुनिया...

26 ममता सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 फरवरी 2021 को कहा कि केरल में हुए गोल्ड स्कैम में...

27 केरल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 फरवरी 2021 को कहा कि प्रदेश में हुए गोल्ड स्कैम में...

27 'दुनिया में जिसे भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए उन्हें हम कराएंगे मुहैया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 31 जनवरी को पुडुचेरी...

साक्षात्कार

'बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण और रोजगार सृजन है': निर्मला सीतारमण 22

मोदी सरकार वंचित वर्गों के हित में हरसंभव कदम उठाएगी: अनुराग ठाकुर 30

लेख

'आत्मनिर्भर भारत' की बुनियाद का बजट
अमित शाह 28

देश की सेहत, सूरत और सीरत संवारने का संकल्प
रघुवर दास 32

अन्य

नए दशक का बुनियादी दृष्टि-पत्र: भाजपा 19

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहेगी 20

तमिलनाडु: एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी भाजपा 27

पश्चिम बंगाल: 'कृषक सुरक्षा सह-भोज' कार्यक्रम संपन्न 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारा किसान अगर और सशक्त होगा, तो कृषि क्षेत्र में प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियां किसानों के फायदे का बाजार बनें, इसके लिए एक हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। यानी, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा।

जगत प्रकाश नड्डा

सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणजी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।

अमित शाह

कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था। परन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणजी ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है। यह आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा।

राजनाथ सिंह

'आत्मनिर्भर भारत' की नींव रखने वाला पहला डिजिटल बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाएगा।

बी. एल. संतोष

16.5 लाख करोड़ रुपये एग्री क्रेडिट आवंटन, सड़कों के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये, 34.5 प्रतिशत की वृद्धि के 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की वृद्धि।

नितिन गडकरी

इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और अमस में नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। देश में नए इकॉनोमिक कॉरिडॉर से भी सड़क परियोजनाओं को मज़बूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकेंगे।

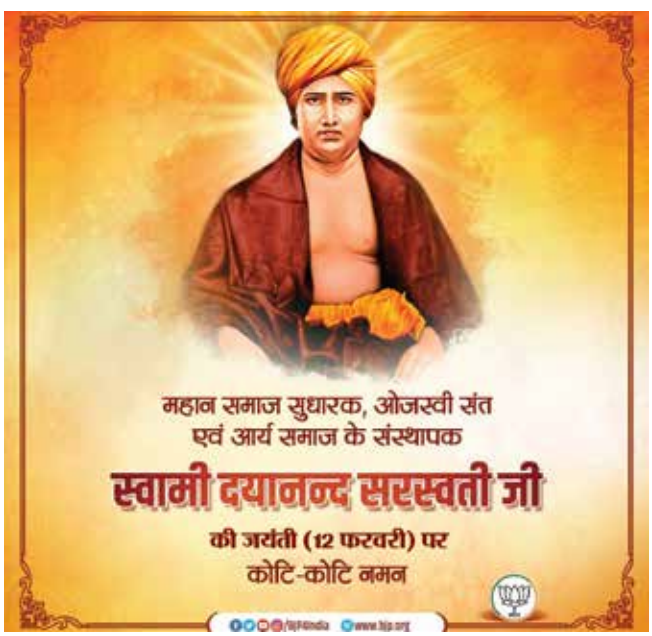

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गुरु रविदास जयंती (27 फरवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

आकांक्षी भारत के लिए सर्वसमावेशी बजट

बजट 2021-22 की पूरे देश में हर वर्ग द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत इस बजट की प्रतीक्षा पूरे देश में बहुत ही बेसब्री से हो रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बजट जन-जन की अपेक्षाओं पर न केवल खरा उतरा है वरन् इसने उन अपेक्षाओं के पार जाकर आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक लंबी छलांग की भूमिका भी तैयार कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो तेजी से पुनर्बहाली के मार्ग पर है, इस भविष्योन्मुखी बजट से और भी अधिक सशक्त हुई है। इस सर्वसमावेशी बजट में न केवल महामारी की चिंताओं के निवारण के लिए देश के सामने सुदृढ़ रणनीति प्रस्तुत है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान को भी आत्मसात् किया गया है। यही कारण है कि आर्थिक विशेषज्ञों से लेकर आमजन तक इस बजट के दूरदर्शी दृष्टिकोण का स्वागत कर रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि इस बजट से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति मिलेगी जिससे देश दहाई के आंकड़े की विकास-दर प्राप्त कर सकेगा।

बजट के छह स्तंभ कोविड के पश्चात् की अर्थव्यवस्था के उन आधारों को संबल प्रदान करते हैं जिससे किसानों की आय को दुगुना, सुदृढ़ अवसंचना का निर्माण एवं युवाओं को अपार अवसर प्राप्त होंगे। एक ओर जहां टीकाकरण अभियान के लिए भारी राशि का आवंटन कर बजट ने महामारी से उबरने के लिए तुरंत के उपाय किए हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में 137 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी कर भविष्य के लिए दिशा सुनिश्चित किया गया है। केन्द्र की 17,788 ग्रामीण 11,024 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ प्रधानमंत्री 'आत्मनिर्भर भारत' स्वास्थ्य योजना, जल आपूर्ति की सर्वव्यापी कवरेज, 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' योजना जन-जन को स्तरीय एवं स्वस्थ जीवन के साथ-साथ पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। साथ ही, राष्ट्रीय अवसंरचना में भारी निवेश के साथ-साथ सड़क एवं राजमार्गों के लिए अब तक सबसे बड़े बजटीय प्रावधान से आत्मनिर्भर भारत की नींव पड़ेगी। भारत-माला परियोजना, आर्थिक कोरिडोर, एक्सप्रेसवे, रेल अवसंरचना, बसों एवं मेट्रो परियोजनाओं से शहरी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा अवसंरचना की मजबूती, बंदरगाह, जलमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस में भारी बजटीय प्रावधान भविष्य के भारत को प्रतिबिंबित करते हैं।

एक ओर जहां टीकाकरण अभियान के लिए भारी राशि का आवंटन कर बजट ने महामारी से उबरने के लिए तुरंत के उपाय किए हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में 137 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी कर भविष्य के लिए दिशा सुनिश्चित किया गया है

बजट में आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जहां कुल लागत का डेढ़ गुणा सुनिश्चित किया गया है, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन एवं मछली पालन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर किसानों के आय को दोगुना करने की दिशा में सुदृढ़ कदम बढ़ाए गए हैं। ग्रामीण अवसंरचना के लिए आवंटन बढ़ाकर, प्रवासी मजदूरों के लिए 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' जैसी योजना एवं मध्यम, छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए विशेष प्रावधानों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। साथ ही, बजट में मानव पूंजी को सुदृढ़ करने के लिए 15000 विद्यालयों में एनईपी के अवयवों के क्रियान्वयन, 100 नए सैनिक विद्यालय, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन एवं एक छत्रक निकाय की स्थापना करने का दूरदर्शी कार्यक्रम है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय तथा कौशल विकास के लिए किए गए बजटीय प्रावधान से देश के मानव पूंजी में गुणात्मक वृद्धि होगी। नवोन्मेष एवं अनुसंधान में निवेश कर संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पूरे बजट में 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' का सिद्धांत व्यवस्था के सरलीकरण एवं प्रभावी, पारदर्शी एवं जनता के लिए सुलभ-सुगम व्यवस्था के निर्माण के प्रयासों में देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा है कि यह आत्मनिर्भरता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण वाली बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी के 'विजन' को दर्शाने वाले इस बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र हैं। इस बजट ने न केवल महामारी की चुनौतियों को अवसर में बदला है, बल्कि यह सही अर्थों में आकांक्षी भारत का सर्वसमावेशी बजट है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

बजट में किसानों की आय में वृद्धि, युवाओं के

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नये दशक का पहला बजट है और अप्रत्याशित कोविड संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल बजट भी है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया। बजट में 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के साथ 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति भी है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है।

बजट में किसानों की आय में वृद्धि, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास आदि पर जोर दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को उबारने, देश में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा कृषि उत्पादों के बाजार की मजबूती के उपायों की घोषणा की।

कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को दोगुना से अधिक कर दिया है। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के

लिए अवसर और मजबूत अवसंरचना पर जोर

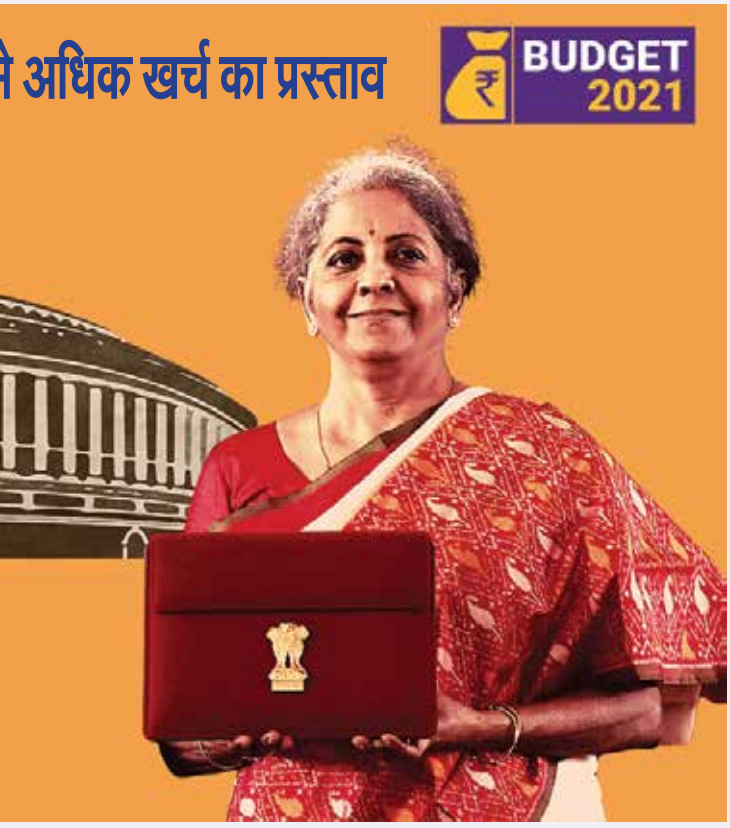

-22 के छह स्तंभ

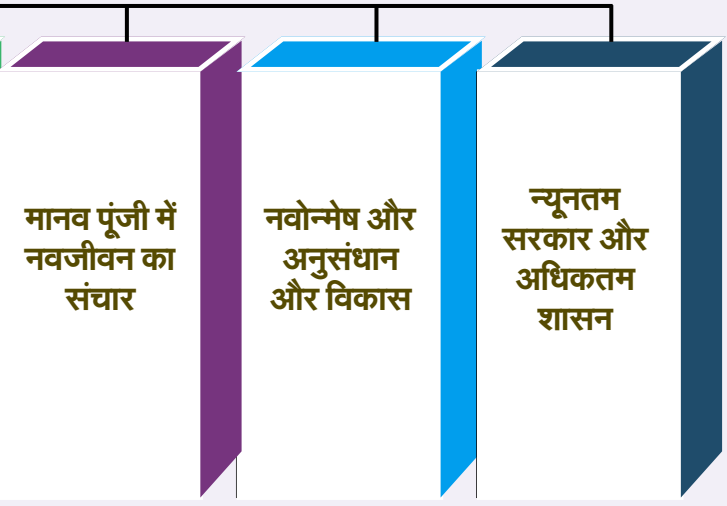

लिये टीकाकरण अभियान के वित्तपोषण तथा देश में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया। सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 94,452 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च को काफी बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से राहत भी दी है। 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।

सस्ते मकानों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने आवास ऋण के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा करने की अवधि को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। इसके साथ ही स्टार्ट-अप के लिए कर अवकाश या छूट को एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया है।

बजट में आयकर के पुनः आकलन के लिये समय-सीमा को घटाकर तीन साल कर दिया गया है। अब तक छह साल पुराने मामलों को दोबारा खोला जा सकता था। पर यदि किसी साल में 50 लाख रुपये या इससे अधिक की अघोषित आय के सबूत मिलते हैं, तो उस मामले में 10 साल तक तक भी पुनः आकलन किया जा सकता है।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे तथा देश की आर्थिक वृद्धि को नीचे खींच रहे सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये।

बजट में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) समेत सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री और निजीकरण के जरिये अगले वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में सूती, रेशम, मक्का छिलका, चुनिंदा रत्नों व →

बजट भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है: नरेन्द्र मोदी

बजट 2021-22 प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाकर आम आदमी के लिए 'इज ऑफ लिविंग' को और भी बेहतर बनाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2021-22 को विकास की वास्तविकता, विश्वास की भावना और भारत के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करनेवाला बताया। उन्होंने एक फरवरी को कहा कि इस कठिन समय में यह बजट दुनिया में एक नए आत्मविश्वास का संचार करेगा।

लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भरता और प्रत्येक नागरिक व वर्ग को शामिल करने की दृष्टि है। श्री मोदी ने बताया कि बजट के सिद्धांतों में शामिल हैं- विकास के लिए नए अवसरों का विस्तार; युवाओं के लिए नए अवसर; मानव संसाधन को नया आयाम देना; बुनियादी ढांचा विकास और नए क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करना।

उन्होंने कहा कि बजट, प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाकर आम आदमी के लिए 'इज ऑफ लिविंग' को और भी बेहतर बनाएगा। बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा।

श्री मोदी ने बजट की प्रस्तुति के कुछ घंटों के भीतर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट का आकार बढ़ाते हुए राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर उचित ध्यान दिया दिया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञों द्वारा बजट के पारदर्शिता आयाम की सराहना की गई है।

चाहे कोरोना महामारी हो या आत्मनिर्भरता अभियान हो, सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि बजट में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण का अंश मात्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सक्रियता से आगे बढ़ चुके हैं और एक अधिक सक्रिय बजट प्रस्तुत किया गया है।

- **बजट में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को मदद मिलेगी**

बजट द्वारा सर्वांगीण विकास पर जोर देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यह धन और कल्याण, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख की विकास जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे हमारे तटीय राज्यों को व्यावसायिक रूप से ताकतवर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बजट असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अपार क्षमता के उपयोग में भी बहुत सहायक होगा।

श्री मोदी ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर बजट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया गया है, जिससे युवाओं को मदद मिलेगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, स्वच्छ जल और अवसरों की समानता से आम आदमी और महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसी तरह बुनियादी ढांचे में अधिक आवंटन और प्रक्रियात्मक सुधारों से रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र और किसान की आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान हैं। किसानों को आसान और अधिक ऋण मिलेगा। एपीएमसी और कृषि अवसंरचना कोष को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिखाता है कि गांव और हमारे किसान इस बजट के केंद्र में हैं।

श्री मोदी ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के आवंटन को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट नए दशक के लिए एक मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए बधाई दी। ■

सभी वर्गों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट: जगत प्रकाश नड्डा

बजट 2021-22 सभी वर्गों खासकर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बजट 2021-22 के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। श्री नड्डा ने एक फरवरी को कहा कि आम बजट 2021-22 डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट है। जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह सभी नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए देश के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि यह बजट असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है जब देश कोरोना संक्रमण के दौर से निकलकर हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह सभी वर्गों खास कर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

श्री नड्डा ने कहा कि ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने कहा कि आम बजट 2021-22 में हेल्थ एंड वेलबिइंग, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एंड आरएंडडी और मिनिमम इंटरवेंशन्स पर विशेष ध्यान दिया गया है जो संपूर्ण भारत के सर्वांगीण विकास पर आधारित है।

- **आम बजट 2021-22 में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाया गया है**

श्री नड्डा ने कहा कि आम बजट 2021-22 में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव लाया गया है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है और शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है जो देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया है। पिछली बार के 92 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य का बजट 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये किया गया है। 64,180 करोड़ रुपये 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। मैं जन-जन की स्वास्थ्य की कामना के प्रति समर्पित इस लोक-कल्याणकारी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि आम बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान यह दिखाता है कि मोदी सरकार कोविड को भारत से जड़ से ख़त्म करने के लिए कितना गंभीर और संवेदनशील है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए

कटिबद्ध है। फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर इसे उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया गया है। साथ ही, मोदी सरकार ने कांग्रेस की यूपीए सरकार से करीब तीन गुना अधिक राशि देश के किसानों के खाते में अब तक पहुंचा दी है।

श्री नड्डा ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के हमारे सीनियर सिटीजंस को IT रिटर्न से राहत देना और पेंशन से आय पर इनकम टैक्स से छूट एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि सब के लिए घर हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाना लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

श्री नड्डा ने कहा कि 1938 से चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव एक सकारात्मक कदम है। इसकी चर्चा बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन यह परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। साथ ही, सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूती प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक केंद्रीय करों में राज्यों को केवल 30 से 35% हिस्सा ही मिल पाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 41 फीसदी हिस्सा मिल सकेगा। इससे राज्यों को विकास कार्यों को गति प्रदान करने में और सहूलियत मिलेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि पिछले बजट में कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि इस वर्ष 5.54 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 34 फीसदी अधिक है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जन-जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले पांच वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन शुरू किया जाना एक अच्छा कदम है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों और हॉयर एजुकेशन काउंसिल का गठन तथा 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा को मजबूत करेगा। रिसर्च के लिए भी 50,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रुपये की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रयास भी काफी उत्तम है। शिक्षा की दृष्टि से यह काफी सराहनीय कदम है।

श्री नड्डा ने कहा कि उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाने का एलान और वर्किंग वुमन के लिए सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। महिला टी-वर्कर्स एवं उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान महिला टी-वर्कर्स को सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कई योजनायें शुरू की हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में 'एक देश-एक राशन योजना' से उन्हें दो वक्त की रोटी की चिंता से मुक्ति मिलेगी। इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ रुपये का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को और मजबूत करेगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल कर इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने का प्रावधान एमएसएमई के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई मजबूती प्रदान करेंगे। लगभग तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास' के मंत्र से प्रेरित केंद्रीय बजट 2021-22 गरीबों, किसानों, एमएसएमई को मजबूती देने वाला, राजकोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला और देश की आर्थिक गति को और तेज करने वाला बजट है।

उन्होंने कहा कि मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। ■

बजट एक 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आम बजट 2021-22 की सराहना करते हुए कहा कि यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पांच मिनी बजट पेश हुए हैं। ये बहुत ही शानदार बजट है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा पूंजीगत व्यय में लगभग 19 फीसद की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि यह 15 वर्षों में रक्षा के लिए पूंजीगत परिव्यय में सबसे अधिक वृद्धि है।

'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करनेवाला बजट: अमित शाह

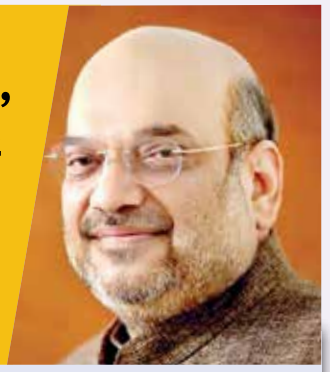

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2021-22 को आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने वाला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है जो प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत', 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडीचर में 34.5% की वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरुप वह पिछले वर्ष के 4.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रुपये हुआ है।

→

आभूषणों, वाहनों के विशिष्ट कलपुर्जों, स्क्रू व नट आदि पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, वायर व केबल, सोलर इन्वर्टर और सोलर लैंप पर भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

इसके अलावा कुछ आयातित उत्पादों पर एक नया कृषि उपकर भी लगाया गया है। बजट में कपास से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक विभिन्न उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ाने की घोषणा की।

सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए कहा है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर देनदारी लाभांश की घोषणा/भुगतान के बाद ही बनेगी।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट संबोधन में कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत के बराबर रह सकता है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 9.5 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है।

केन्द्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें निम्न हैं:

1. स्वास्थ्य और खुशहाली

- बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपये का व्यय रखा गया है जबकि 2020-21 में यह 94,452 करोड़ रुपये था। यह 137 प्रतिशत की भारी वृद्धि
- स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए तीन क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित– निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक
- स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए कदम

टीका

- वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये
- मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में पांच राज्यों के साथ देशभर में आ जाएगी- जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा

आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज

जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए पांच वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपये का परिव्यय– इसे निम्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा

- 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन
- सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति
- 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन

स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत

- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन

प्रदूषण

- वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराना

स्क्रैपिंग नीति

- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति
- ऑटोमोटिड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांचः
- निजी वाहनों के मामले में 20 वर्ष के बाद
- वाणिज्यिक वाहनों के मामलें में 15 वर्ष बाद

2. वास्तविक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

- 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था
- आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाना
- विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने के लिए सक्षमता और अत्याधुनिकी प्रौद्योगिकी रखने की आवश्यकता
- प्रमुख क्षेत्रों में व्यापकता और आकार लाना
- युवाओं को नौकरियां प्रदान करना

कपड़ा

- पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क (मित्र) योजना
- तीन वर्ष की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे
- कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन को तेज करने के लिए पीएलआई योजना

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का विस्तार करके इसमें 7400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है
- 1.10 लाख करोड़ रुपये की करीब 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं

संस्थागत बुनियादी ढांचे का गठन: अवसंरचना वित्त पोषण

- विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है, ताकि यह बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें
- तीन वर्षों में प्रस्तावित डीएफआई के अंतर्गत कम-से-कम 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी पोर्टफोलियो हों
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा आईएनवीआईटी और आरईआईटी का ऋण वित्तपोषण संगत विधानों में उपयुक्त संशोधन करके पूरा किया जाएगा

परिसम्पत्तियों पर जोर

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी
- महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मुद्रीकरण उपाय

1. 5,000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ पांच परिचालित टोल सड़कें एनएचएआईआईएनवीआईटी को हस्तांतरित की जा रही है
2. 7,000 करोड़ रुपये मूल्य की ट्रांसमिशन परिसम्पत्तियां पीजीसीआईएलआईएनवीआईटी को हस्तांतरित की जाएंगी
3. रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर की परिसम्पत्तियों को चालू होने के बाद प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा
4. विमान पत्तनों के प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत की जाएगी
5. अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परिसम्पत्तियों के परिसम्पत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा

- गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल की तेल और गैस पाइपलाइनें
- टियर II और III शहरों में एएआई विमानपत्तन
- अन्य रेलवे बुनियादी ढांचा परिसम्पत्तियां

- केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम और नैफेड जैसे सीपीएसई की वेयरहाउसिंग परिसम्पत्तियां
- खेल स्टेडियम

पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि

- वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि कर 5.54 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जो 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपये से 34.5 प्रतिशत अधिक है
- राज्यों और स्वायत्तशासी संगठनों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी
- पूंजीगत व्यय की अच्छी प्रगति को देखते हुए परियोजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है

सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना

- सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक आवंटन—जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपये पूंजी जुटाने के लिए
- 5,35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू
- 3,800 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण हो चुका है
- मार्च, 2022 तक 8,500 किलोमीटर लम्बी सड़कें और बनाई जाएगी
- 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे भी मार्च, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे

आर्थिक गलियारे बनाने की योजना

- तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 3,500 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा
- केरल में 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1,100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण
- पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये लागत का 675 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य
- असम में 19,000 करोड़ रुपये लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य इस समय जारी है। राज्य में अगले तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये लागत के 1,300 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा

रेलवे अवसंरचना

- रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए
- भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना (2030) : 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए
- दिसम्बर, 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करना
- ब्रॉड-गेज मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण 2021 के अंत तक 72 प्रतिशत यानी 46,000 आकेएम तक पहुंचाना
- पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी को जून 2022 तक चालू करना। इससे परिवहन लागत कम होगी और मेक-इन-इंडिया रणनीति को समर्थ बनाया जा सकेगा

शहरी अवसंरचना

- सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करके और सिटी बस सेवा प्रारंभ कर शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी
- सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी
- इसके तहत नवोन्मेषी पीपीपी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत निजी क्षेत्र के परिचालकों को 20,000 से ज्यादा बसों की खरीद, परिचालन, रख-रखाव और वित्त का प्रबंधन करने का अवसर मिलेगा
- इस योजना से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवागमन अधिक आसान हो जाएगा
- देश में इस समय करीब 702 किलोमीटर पारम्परिक मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर लम्बी मेट्रो तथा आरआरटीएस लाइनों का निर्माण किया जा रहा है
- सरकार 'मेट्रो लाइट' और 'मेट्रो नियो'– दो नई प्रौद्योगिकियां लागू कर आम लोगों को काफी कम कीमत पर और पहले जैसा अनुभव देने वाली मेट्रो रेल प्रणाली देना चाहती है। यह प्रणाली

बजट में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए 51.65% की वृद्धि: थावरचंद गहलोत

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने बजट 2021-22 की प्रशंसा करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 51.65% की वृद्धि की है जो कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूल मंत्र को सिद्ध कर रहा है।

टियर-2 और टियर-1 शहरों के आस-पास बसे इलाकों में आसान और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी

विद्युत अवसंरचना

- पिछले 6 सालों में स्थापित क्षमता में 139 गीगा वाट्स का इजाफा किया गया है और 1.41 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं, 2.8 करोड़ अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिये गये हैं
- ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जायेगा जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़े और उपभोक्ताओं को विकल्प चुनने का अवसर मिले
- आने वाले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपये के व्यय से एक परिष्कृत और सुधार आधारित तथा परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना शुरू की जायेगी
- 2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जायेगा

पत्तन, नौवहन, जलमार्ग

- वित्त वर्ष 2021-22 में बड़े-बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत प्रमुख पत्तनों द्वारा 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी, जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी

अब तक का पहला बजट, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी: नितिन गडकरी

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय बजट 2021-22 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आम बजट देश के इतिहास में अब तक का पहला ऐसा बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। साथ ही श्री गडकरी ने राजमार्ग सेक्टर के लिए व्यय प्रावधान बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ रुपए किये जाने का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा राजमार्गों के मुद्रीकरण पर अधिक जोर से देश में सड़कों के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी।

- आने वाले 5 वर्षों में भारतीय शिपिंग कंपनियों को मंत्रालयों और सीपीएसई के वैश्विक टेंडरों में 1624 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जायेगा
- अगले तीन वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जायेगा
- जम्मू-कश्मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जायेगी
- एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जायेगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी

बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना

- बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण से सुरक्षा को बढ़ाना

तनावग्रस्त परिसंपत्ति का समाधान

- एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जायेगा

पीएसबी का पुन: पूंजीकरण

- पीएसबी की वित्तीय क्षमता को और अधिक समेकित करने के लिए 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त पुनः पूंजीकरण किया जायेगा

कंपनी मामले

- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) कानून 2008 को अपराध मुक्त बनाया जायेगा
- कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया जायेगा जिसके तहत प्रदत्त पूंजी के लिए उनकी न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होने के स्थान पर 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तथा कारोबार की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने के स्थान पर 20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना तय किया जायेगा
- स्टार्टअप और नवाचार के लिए काम करने वालों को ओपीसी की मंजूरी देते हुए एकल व्यक्ति कंपनी के निगमन को प्रोत्साहित किया जायेगा

विनिवेश एवं रणनीतिक बिक्री

- बजट अनुमान 2020-21 में विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियां
- बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि का रणनीतिक विनिवेश 2020-21 में पूरा हो जाएगा
- आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा
- 2021-22 में एलआईसी का आईपीओ
- रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति को मंजूरी
- सीपीएसई ने 4 रणनीतिक क्षेत्रों में निजीकरण को स्वीकार किया
- नीति आयोग रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीएसई की नई सूची पर काम करेगा
- केंद्रीय निधियां उपयोग करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों के विनिवेश के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा
- बेकार पड़ी जमीन के मौद्रिकरण के लिए कंपनी के रूप में विशेष उद्देश्य वाहन
- बीमार और हानि उठा रही सीपीएसई को समय पर बंद करने के लिए संशोधित कार्यविधि की शुरुआत

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

कृषि

- सभी जिन्सों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना
- स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा। 1241 गांवों में 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं
- वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पशुपालन डेरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये की जाएगी
- सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10 हजार करोड़ रुपये की गई
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले
- ई-नाम के माध्यम से लगभग 1.68 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया गया और 1.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य का व्यापार किया गया। 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा

मछली पालन

- समुद्र और देश में आधुनिक मछली बंदरागाहों और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए निवेश
- पांच प्रमुख मछली बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

प्रवासी कामगार और मजदूर

- देश में कहीं भी राशन का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना- इसका प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है
- योजना लागू होने से अब तक 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 86 प्रतिशत लाभार्थियों को शामिल किया गया
- बकाया 4 राज्य भी अगले कुछ महीनों में इसमें एकीकृत हो जाएंगे

- गैर संगठित मजदूरों, प्रवासी कामगारों विशेष रूप से इनके लिए सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल

श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी

- नावों और प्लेटफॉर्मो पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ
- सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा
- महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाजत होगी, जिसमें वह रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी

स्टैंडअप इंडिया स्कीम

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम
- मार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया
- इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दिये जाने वाले ऋणों को शामिल किया जाए
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जोकि इस वर्ष के बजट अनुमान का दोगुना है

4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार

विद्यालय शिक्षा

- 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वह अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरणपरक विद्यालय के रुप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे
- गैर-सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे

उच्चतर शिक्षा

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे
- सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय हो सके
- लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एक्लव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य
- ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करना
- पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करना
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई
- 2025-2026 तक 6 वर्षों के लिए 35,219 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की गई
- इससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ मिलेगा
- युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रैन्टिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया
- अभियांत्रिकी में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों की शिक्षा-उपरांत अप्रैन्टिसशिप, प्रशिक्षण की दिशा में मौजूदा राष्ट्रीय अप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के पुनर्सृजन के लिए 3,000 करोड़ रुपये

5. नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए जुलाई 2019 में एक कार्यप्रणाली तैयार की गई थी
- पांच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
- संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करना और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना
- भुगतान के डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की प्रस्तावित योजना के लिए 15,00 करोड़ रुपये
- पहला मानवरहित यान का प्रक्षेपण दिसंबर, 2021 में होगा

6. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

- तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों में सुधार लाने के उपाय
- राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग का पहले ही प्रस्ताव किया जा चुका है ताकि 56 संबंद्ध स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की पारदर्शिता और दक्षता पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके

- राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवायफरी आयोग विधेयक नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता और प्राशसनिक सुधार के लिए प्रस्तुत किया गया
- सीपीएसई के साथ अनुबंध विवाद के तुरंत निपटारे के लिए विवाद निपटान तंत्र का प्रस्ताव
- भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित

व्यय की गुणवत्ता बरकरार

- व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी गई है, जबकि कैपिटल व्यय का अनुमान 2020-21 के बजटीय अनुमान के अनुसार 4.12 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा 2020-21 में वास्तविक अनुमान के अनुसार 4.39 लाख करोड़ रुपये हैं
- 30.42 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक बजट अनुमान व्यय की अपेक्षा व्यय के लिए मूल अनुमान 34.50 लाख करोड़ रुपये है
- 2021-22 के बजट अनुमान में अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, इसमें 5.5 लाख करोड़ रुपये कैपिटल व्यय के लिए शामिल है और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है
- 2021-22 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत अनुमानित है। सरकार की उधारी, बहुपक्षीय उधारी, लघु बचत कोष और लघु अवधि की उधारी से प्राप्त धन के कारण 2020-21 के वास्तविक अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है
- अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं
- 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत तक करने के लिए राजकोषीय संकोचन के मार्ग पर अग्रसर होने की योजना है

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

- बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करेगा

विवादों को कम करना, समाधान आसान

- मामलों को दोबारा खोलने की समय-सीमा घटाकर 6 वर्ष से 3 वर्ष की गई
- कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 साल तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है

सबके लिए मकान का समर्थन

- सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा
- सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई
- सस्ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा

कोविड-19 महामारी के दौरान उपलब्धियां

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)

- 2.76 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज
- 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस
- 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और ज़रुरतमन्दों को सीधे नकद धनराशि का अंतरण

आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0):

- 23 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा
- पीएमकेजेवाई, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0, 2.0 और 3.0) इसके अलावा पांच छोटे बजटों जैसी घोषणाएं भी बाद में की गईं
- आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जोकि जीडीपी के 13 प्रतिशत से ज्यादा है

संरचनात्मक सुधार

- एक देश, एक राशन कार्ड
- कृषि और श्रम सुधार
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की पुनः परिभाषा
- खनन क्षेत्र का वाणिज्यीकरण
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

यह बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है: अर्जुन मुंडा

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट है, जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है, जो पूर्व में कभी नहीं थी। श्री मुंडा ने कहा कि बजट में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ गांवों तक सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए भी कारगर प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान के लिए धन्यवाद। इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं
- कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की ताजा स्थिति
- 2 मेड-इन-इंडिया टीके– कोविड-19 के खिलाफ भारत के नागरिकों के साथ-साथ 100 से भी अधिक देशों के नागरिकों को चिकित्सीय सुरक्षा मुहैया कराने में कारगर साबित
- 2 या उससे भी अधिक नए टीके जल्द उपलब्ध होने की आशा
- प्रति मिलियन न्यूनतम मृत्यु दर और न्यूनतम सक्रिय मामले

2021- भारतीय इतिहास में उपलब्धियों का वर्ष

- भारत की आजादी का 75वां वर्ष
- भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे
- 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे
- स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना का वर्ष
- ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब भारत की बारी
- चंद्रयान-3 मिशन का वर्ष
- हरिद्वार महाकुंभ

'आत्मनिर्भर भारत' के लिए विजन

- आत्मनिर्भरता कोई नया आइडिया नहीं है, प्राचीन भारत आत्मनिर्भर था और पूरी दुनिया का एक कारोबारी केंद्र था
- 'आत्मनिर्भर भारत' यह 130करोड़ भारतीयों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। ■

नए दशक का बुनियादी दृष्टि-पत्र: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं राज्य प्रभारियों की वर्चुअल बैठक में पारित प्रस्ताव पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं राज्य प्रभारियों की एक वर्चुअल बैठक 03 फरवरी, 2021 को आहूत की गई थी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी. एल. संतोष सहित पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, राज्यों के महामंत्री (संगठन) एवं राज्यों के पार्टी प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि को समर्पित सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी तथा 'ईज ऑफ लिविंग' की बुनियाद रखने वाले आम बजट 2021-22 पर एक प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में कहा गया कि कोविड काल की कठिन परिस्थिति के बीच दूरगामी परिणाम देने वाले इस 'सर्वजन हिताय' और सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं ईज ऑफ लिविंग की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाले आम बजट 2021-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व का अभिनंदन करती है और वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई देती है।

- **'सर्वजन हिताय' और सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं ईज ऑफ लिविंग की परिकल्पना को चरितार्थ करने वाला आम बजट**

प्रस्ताव में कहा गया कि आम बजट 2021-22 स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, नवाचार और शोध, मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पूंजी व अवसंरचना एवं मानव जीवन में सुगमता का संचार के छह स्तंभों को रेखांकित करने वाला नए दशक का बुनियादी दृष्टि-पत्र है। पिछले छह वर्षों के शासन काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के उन सभी आयामों को स्पर्श कर रहा है, जो देश के सामान्य जन की आकांक्षा थे। यह नए दशक में आकांक्षी और आशावान भारत को नई उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान करने वाला बजट सिद्ध होगा। कोविड संक्रमण की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की इस क्षमता को पहचानते 'आत्मनिर्भर भारत का संकल्प' देश के सामने रखा रखा। यह बजट आत्मनिर्भरता के उसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की मजबूत और दूरगामी कड़ी है।

प्रस्ताव में कहा गया कि हम नहीं भूल सकते कि यह बजट एक ऐसे समय में आया है, जब दुनिया पूरी तरह से कोरोना की चुनौती से निकल भी नहीं पाई है, किंतु यह भी सच है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जिस संजीदगी, संवेदना और सजगता का परिचय दिया, वह अपने आप में इतिहास में दर्ज एक मिसाल बन गया है। इस दौरान करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन और करोड़ों लाभार्थियों के खातों में विभिन्न योजनाओं का लाभांश पहुंचाने का काम इस दौरान हुआ है। हमने दो-दो 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की योजनाबद्ध शुरुआत भी हो चुकी है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किये गये कार्यों की भी सराहना करती है।

आम बजट 2021-22 में स्वास्थ्य की संरचना में बेहतरी, कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ता, किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय को दोगुना करने की प्रतिबद्धता, सड़क और परिवहन क्षेत्र को और विस्तार देने का लक्ष्य, आधारभूत संरचना को मजबूती, छोटे व मध्यम कारोबार के लिए संबल, गांवों के विकास के लिए बजटीय प्रस्ताव तथा शिक्षा क्षेत्र में नए निर्माणों तथा अवसरों, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर भरने मे राहत सहित सभी क्षेत्रों की बेहतरी के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो यह बजट सबके लिए 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला 'आत्मनिर्भर भारत' का बजट है।

प्रस्ताव में कहा गया कि छह वर्षों के अब तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कृषि विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं। देश के किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने पिछली बार की तुलना बढ़ोतरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व का अभिनंदन करती है। ■

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहेगी

'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के जरिए दी जा रही आवश्यक सहायता के बल पर अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है

वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है। व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत देश में 'V' आकार में आर्थिक विकास संभव होगा।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष के अपेक्षा से कम रहने वाले संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ कोविड-19 के उपचार में कारगर टीकों का उपयोग शुरू कर देने से देश में आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्य होने की बदौलत ही आर्थिक विकास फिर से तेज रफ्तार पकड़ पाएगा।

देश के बुनियादी आर्थिक तत्व अब भी मजबूत हैं क्योंकि लॉकडाउन को क्रमिक रूप से हटाने के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन के जरिए दी जा रही आवश्यक सहायता के बल पर अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। इस मार्ग पर अग्रसर होने की बदौलत वर्ष 2019-20 की विकास दर की तुलना में वास्तविक जीडीपी में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी। जिसका मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था दो वर्षों में ही महामारी पूर्व स्तर पर पहुंचने के साथ-साथ इससे भी आगे निकल जाएगी।

ये अनुमान दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप ही हैं जिनमें कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8 प्रतिशत रहेगी। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

- **वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है**

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 'सौ साल में एक बार' भारी कहर ढाने वाले इस तरह के गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अत्यंत परिपक्वता दिखाते हुए जो विभिन्न नीतिगत कदम उठाए हैं उससे विभिन्न देशों को अनेक महत्वपूर्ण सबक मिले हैं जिससे वे अदूरदर्शी नीतियां बनाने से बच सकते हैं। इसके साथ ही भारत के ये नीतिगत कदम दीर्घकालिक लाभों पर फोकस करने के महत्वपूर्ण फायदों को भी दर्शाते हैं।

राजकोषीय और मौद्रिक सहायता

भारत ने नियंत्रण, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों के चार स्तम्भों वाली अनूठी रणनीति अपनाई। देश में उभरते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित ढंग से राजकोषीय और मौद्रिक सहायता दी गई। इसके साथ ही इस दौरान क्रमिक रूप से अनलॉक करते समय संबंधित सरकारी उपायों के राजकोषीय प्रभावों और कर्जों की निरंतरता को भी ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक असुरक्षित पाए गए लोगों को आवश्यक सहायता दी गई और इसके साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उपभोग एवं निवेश को काफी बढ़ावा मिला। अनुकूल मौद्रिक नीति से पर्याप्त तरलता सुनिश्चित हुई। इसी तरह मौद्रिक नीति के कदमों का लाभ प्रदान करते समय कर्जदारों को अस्थायी मोहलत के जरिए तत्काल राहत प्रदान की गई।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर (-) 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रथम छमाही में जीडीपी में 15.7 प्रतिशत की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में 0.1 प्रतिशत की अत्यंत कम गिरावट को देखते हुए ही यह अनुमान लगाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों पर नजर डालने पर यही पता चलता है कि कृषि क्षेत्र अब भी आशा की किरण है, जबकि लोगों के आपसी संपर्क

वाली सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे जिनमें धीरे-धीरे सुधार देखे जा रहे हैं। सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात के बल पर ही आर्थिक विकास में और ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है।

जैसाकि अनुमान लगाया गया था, लॉकडाउन के कारण प्रथम तिमाही में जीडीपी में (-) 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं, बाद में 'V' आकार में वृद्धि यानी निरंतर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम गिरावट और सभी महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों में हो रही बेहतरी में प्रतिबिंबित होती है। गत जुलाई माह से ही 'V' आकार में आर्थिक बेहतरी निरंतर जारी है जो प्रथम तिमाही में भारी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में जीडीपी में दर्ज की गई अपेक्षाकृत कम गिरावट में परिलक्षित होती है।

भारत में महामारी के प्रकोप के बाद बढ़ती गतिशीलता पर ध्यान देने पर यह पता चलता है कि विभिन्न संकेतक जैसे कि ई-वे बिल, रेल माल भाड़ा, जीएसटी संग्रह और बिजली की मांग बढ़कर न केवल महामारी पूर्व स्तरों पर पहुंच गई है, बल्कि पिछले वर्ष के स्तरों को भी पार कर गई है। राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को फिर से चालू कर देने और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। मासिक जीएसटी संग्रह से यह पता चलता है कि देश में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को किस हद तक उन्मुक्त कर दिया गया है। वाणिज्यिक प्रपत्रों की संख्या में तेज वृद्धि, यील्ड में कमी आने और एमएसएमई को मिले कर्जों में उल्लेखनीय वृद्धि से यह पता चलता है कि विभिन्न उद्यमों को अपना अस्तित्व बनाए रखने और विकसित होने के लिए व्यापक मात्रा में कर्ज मिल रहे हैं।

• सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो वित्त वर्ष 2020-21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है

कृषि क्षेत्र की उल्लखेनीय वृद्धि

समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की बदौलत वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से लगे तेज झटकों के असर काफी कम हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के साथ-साथ दूसरी तिमाही में भी 3.4 प्रतिशत रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो वित्त वर्ष 2020-21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है।

जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति और कर्जों की घटती मांग के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक कर्जों का स्तर निम्न स्तर पर बना रहा। हालांकि, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए कर्ज अक्टूबर, 2019 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2020 में 7.4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गए। अक्टूबर, 2020 के दौरान निर्माण, व्यापार एवं आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में कर्ज प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में बैंक कर्ज का प्रवाह धीमा ही बना रहा। सेवा क्षेत्र को कर्ज प्रवाह अक्टूबर, 2019 के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर, 2020 में 9.5 प्रतिशत हो गया।

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी

बाह्य क्षेत्र से भी भारत में विकास को काफी सहारा मिला। दरअसल, चालू खाते में अधिशेष वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा, जो सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि और कम मांग की बदौलत संभव हुआ। इस वजह से निर्यात (वाणिज्यिक निर्यात में 21.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ) की तुलना में आयात (वाणिज्यिक आयात में 39.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ) में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा भंडार इतना अधिक बढ़ गया जिससे 18 माह के आयात को कवर किया जा सकता है।

भारत वित्त वर्ष 2020-21 में भी पसंदीदा निवेश गंतव्य बना रहा, जो वैश्विक निवेश को शेयरों में लगाने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बेहतरी आने की संभावनाओं के मद्देनजर संभव हो पाया है। देश में शुद्ध एफपीआई प्रवाह नवम्बर, 2020 में 9.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक मासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जो निवेशकों में फिर से जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ने, वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति को उदार बनाने और घोषित किए गए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों के मद्देनजर अनुकूल यील्ड हासिल करने पर विशेष जोर देने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से संभव हुआ। भारत वर्ष 2020 में विभिन्न उभरते बाजारों में एकमात्र ऐसा देश रहा जहां इक्विटी में एफआईआई का प्रवाह हुआ। ■

'बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण और रोजगार सृजन है'

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सदी की सबसे बड़ी महामारी की पृष्ठभूमि में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर साल 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। 'कमल संदेश' के सह संपादक संजीव कुमार सिन्हा और राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ बातचीत में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट की कुछ मुख्य बातों पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कैसे सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सड़क, बंदरगाह, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा का निर्माण, शिक्षा और देश के समग्र विकास जैसे विषयों पर जोर देकर इनमें तेजी लाना चाहती है। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंश:

• आपने इस बजट को सदी की सबसे बड़ी महामारी 'कोरोनो वायरस' की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। महामारी के बाद हर कोई इस बारे में आशंकित था कि बजट 2021-22 क्या लेकर आयेगा। हालांकि, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत इस सर्व-समावेशी बजट ने बहुत लोगों को आश्चर्यचकित किया है। इस बजट के साथ आप किन प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं?

इस बजट का प्रमुख उद्देश्य छह स्तंभों पर आधारित है। सबसे पहले, 'स्वास्थ्य एवं खुशहाली', हमने स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें तीन क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा- निवारक, उपचारात्मक और सेहत। इसमें स्वच्छता और प्रदूषण पर नियंत्रण जैसे कारक भी शामिल हैं। दूसरा है, 'भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना'। इसके तहत हम संस्थागत संरचनाओं का निर्माण, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, और मजबूत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। बुनियादी ढांचे पर व्यय के गुणक प्रभाव व्यापक विकास सुनिश्चित करेगा।

तीसरा 'आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास' में किसानों की आय को बढ़ाना, मत्स्य पालन को विकसित करना और सभी के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाना शामिल हैं। इसमें प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक समर्पित पोर्टल जैसे कदम भी शामिल हैं जो निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट, मजदूरों के लिए योजनाएं और भोजन आदि की प्रासंगिक जानकारी देगा। चौथा स्तंभ, 'मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना' है। यहां हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को 'न्यू इंडिया' के विकास की कहानी- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवाओं आदि में योगदान करने का समान अवसर मिले। यह सभी को समान शिक्षा के अवसर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।

'नवाचार और अनुसंधान व विकास' पांचवा स्तंभ है। अन्य बातों के अलावा, इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की शुरुआत शामिल है, जिसमें देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 50000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। छठा और अंतिम स्तंभ है 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन', जो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का आदर्श वाक्य रहा है, जो नागरिकों को बिना किसी हस्तक्षेप के आसानी से जीवन-यापन करने के लिए विभिन्न उपाय करता है। फिर चाहे इसके लिए सरकार को न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अधिक प्राधिकरणों को स्थापित करने की बात हो या सीपीएसई के साथ काम करने वाली कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी का मुद्दा हो।

• स्वास्थ्य बजट को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाना, यह एक बहुत ही साहसिक कदम था। वहीं कोविड टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। क्या आपको लगता है कि यह भारी भरकम आवंटन स्वास्थ्य क्षेत्र और इसके बुनियादी ढांचे को बदल देगा?

हां, क्योंकि हमने स्वास्थ्य के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह समग्र है। जैसाकि पहले बताया गया है कि हम तीन क्षेत्रों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं: निवारक, उपचारात्मक और सेहत। इसमें 112 आकांक्षी जिलों में पोषण कार्यक्रमों में सुधार के लिए गहन रणनीति अपनाने के साथ पोषण मापदंडों पर भी जोर दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह बजट स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करने पर महत्व देता है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में जल-आपूर्ति के साथ-साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कार्य करेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए वायु-प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

• 2014 से ही हमने किसान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में बदलाव शुरू किया है। फसल बीमा योजना को अधिक किसान-हितैषी बनाने पर बल दिया गया। पीएम-किसान योजना को लागू किया गया

• मेगा टेक्सटाइल पार्कों और अवसंरचना के लिए विशाल बजट आवंटन की घोषणा के पीछे क्या विचार है? यह कुछ राज्यों से भारी श्रम पलायन समस्या के लिए बहुप्रतीक्षित समाधान का कैसे माध्यम बनता है और किस प्रकार रोजगार के अवसर पैदा करेगा?

पीएलआई योजना के साथ हम उन प्रमुख उद्योगों को मजबूत कर रहे हैं, जहां हमें बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं। कपड़ा उद्योग भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। हम उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते हैं और प्रस्तावित मेगा इनवेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्कों के माध्यम से निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। इसके पीछे रोजगार सृजन एक प्रमुख लक्ष्य है। अवसंरचना पर खर्च करके हम संपत्ति निर्माण में निवेश करना चाहते हैं जैसे कि सड़क, बंदरगाह आदि। इसका कई गुना प्रभाव पड़ने वाला है। यह मुख्य उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील, बिजली, आदि में मांग बढ़ाएगा। यह बदले में रोजगार पैदा करेगा। जबकि एक अवसंरचना परियोजना को पूरा होने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन इससे नौकरियां तुरंत उत्पन्न होती हैं। चूंकि चल रही और घोषित परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, तो यह कदम सभी राज्यों के श्रमिकों को लाभान्वित करने जा रहा है।

• इस साल के बजट में कृषि क्षेत्र और कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान हैं। क्या कृषि सुधारों का विरोध इसमें बाधक बन सकता है?

केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार को लागू करने में विपक्षी दलों को साथ लिया है। वास्तव में सरकार जिन सुधारों को लागू कर रही है, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुद कहा था कि अगर वह चुनाव जीत जाती तो ऐसा ही करती! कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा-पत्र में कहा कि वह एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करेगी और कृषि उपज में व्यापार (निर्यात और अंतर-राज्य व्यापार) को सभी प्रतिबंधों से मुक्त करेगी।

2014 से ही हमने किसान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में बदलाव शुरू किया है। फसल बीमा योजना को अधिक किसान-हितैषी बनाने पर बल दिया गया। पीएम-किसान योजना को लागू किया गया। सरकार ने बार-बार तीनों कृषि कानूनों पर संवाद आमंत्रित किए हैं। अब तक, 12 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और सरकार आगे भी खुले मन से बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार इन कानूनों को लेकर विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार इस स्तर तक खुले मन से बात करने को तैयार है।

इस वर्ष की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत गांवों में संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा रहा है। अब तक 1,241 गांवों में लगभग 1.80 लाख संपत्ति-मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को इसके तहत आने का प्रयास किया जा रहा है।

किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड का आवंटन भी 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना किया गया।

'आपरेशन ग्रीन स्कीम' का दायरा बढ़ाया गया है, जो टमाटर, प्याज और आलू पर लागू था, उसमें 22 खराब होने वाले उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, बजट में 1,000 नयी मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किये जाने का प्रावधान है।

एपीएमसी मंडियों को कृषि अवसंरचना निधि से पैसा उपलब्ध करवाया जा सकेगा, जिसका प्रयोग मंडियों की अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा। मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास में पर्याप्त निवेश की घोषणा की गई हैं। सरकार नदियों और जलमार्गों के किनारे अंतर्देशीय मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली पकड़ने के केंद्र विकसित करेगी।

• जैसाकि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने भारत में व्यावसायिक वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है। महामारी के बाद की परिस्थितियों में प्रस्तुत इस बजट के बाद इन वर्गों ने राहत की सांस ली है। व्यावसायिक वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है?

जैसा कि मैंने पिछले बजट में कहा था और सरकार ने पिछले वर्ष में दिखाया है और इस बजट में भी, सरकार देश के व्यापारिक वर्ग के समर्थन में है। कोविड के दौरान सरकार ने एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के रूप में आपातकालीन ऋण की पेशकश की, जिसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आपातकालीन ऋण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण के तौर पर 20,000 करोड़ रुपये प्रदान किए। 'आत्मनिर्भर पैकेज' के बाद शुरू होने वाले स्टार्टअप एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं। घोषित किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक यह था कि भारत-पंजीकृत कंपनियां अब अधिसूचित वैश्विक एक्सचेंजों में प्रारंभिक आईपीओ की पेशकश कर सकती हैं। इस प्रकार भारतीय स्टार्टअप अब वैश्विक स्तर पर मौजूद सार्वजनिक और निजी बाजारों की पूंजी का उपयोग कर सकते हैं।

रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार का समग्र जोर नए निवेशकों सहित भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा करने पर है। 74 प्रतिशत एफडीआई सीमा भी नए उपक्रमों के लिए वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाना आसान बनाती है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के पीछे तकनीकी नवाचार पर जोर दे रही है, जिससे नई कंपनियों के लिए इस नए क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे समय में जब भारत पहले से ही अंतरिक्ष क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, निजी भागीदारी की अनुमति देने के सरकार के फैसले से इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक नवाचार के नए रास्ते खुल गए हैं और नई कंपनियां इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं।

• इस ऐतिहासिक बजट के बाद, आप आर्थिक सुधार के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहु-प्रतीक्षित विकास को कैसे देखती हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री का 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प कितना कारगर है?

भारतीय शेयर बाजार ने केंद्रीय बजट 2021 की प्रशंसा की है, जिसका प्रमाण बीएसई सेंसेक्स में आई तेजी है।

परिणामस्वरूप इंट्रा-डे ट्रेड में 2,000 से अधिक अंक की बढ़त और एनएसई निफ्टी 14,000 के स्तर तक पहुंच गया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश संकेतक न केवल सकारात्मक हो गए हैं, बल्कि वे कोरोना पूर्व की स्थिति से बेहतर हो गए। जनवरी, 2021 में जीएसटी संग्रह 1.19 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक का सबसे अधिक कर संग्रह है। यह दिसंबर 2020 में एकत्र किए गए 1.15 लाख करोड़ रुपये के बाद का आंकड़ा है, जो अपने आप में पहले ही उच्चतम संग्रह का रिकार्ड बना चुका था। भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मजबूती के साथ जनवरी में 57.7 था, जो तीन महीने का इसका सबसे उच्चतम स्तर था। दिसंबर, 2020 और नवंबर, 2020 में विनिर्माण पीएमआई क्रमशः 56.4 और 56.3 था।

दिसंबर, 2020 में पेट्रोलियम की खपत 1.85 करोड़ मीट्रिक टन रही, जो पिछले साल के आसपास ही है। दिसंबर, 2019 की तुलना में दिसंबर, 2020 में रेलवे माल ढुलाई में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूपीआई लेनदेन भी उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो जनवरी, 2021 में मूल्य के हिसाब से 4.31 लाख करोड़ रुपये और संख्या के हिसाब से 230 करोड़ रुपये है। यह जनवरी, 2020 की तुलना में मूल्य और संख्या के हिसाब से लगभग दोगुना है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 में 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में सुधार की ओर इशारा करता है जो कि पूर्ववर्ती तिमाही में 47.3 प्रतिशत से दूसरी तिमाहीः 2020-21 में 63.3 प्रतिशत रहा। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हाल के महीनों में बढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली तेजी को दिखाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास के संकेत के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत के लिए 11.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दोहरे अंकों की वृद्धि के अनुमान के साथ आगे बढ़ रहा है। ■

'हमारे एक-एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं'

भारत जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जनवरी को कहा कि कोरोना महामारी का सालभर मजबूती से मुकाबला करने के बाद भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, लेकिन इस सबके बीच 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लालकिले पर हुई घटना से देश बहुत दुःखी हुआ।

श्री मोदी ने आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 73वीं कड़ी को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है और भारत जितना सक्षम होगा, उतना ही अधिक दुनिया को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को 'पराक्रम दिवस' के तौर पर मनाए जाने और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की 'शानदार परेड' का भी जिक्र किया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शृंखला में मिली जीत का भी उल्लेख किया।

इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में हुए संबोधन और पद्म पुरस्कारों की घोषणा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है और अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है।

श्री मोदी ने कहा कि यानी, जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनजाने चेहरों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। कोरोना के खिलाफ चल रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि आज वह दवाओं और टीके को लेकर आत्मनिर्भर है।

उन्होंने कहा कि यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत, जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन।

श्री मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण अभियान भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 'मेड इन इंडिया' टीके आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक हैं ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया और इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, ये प्रयास जारी रहेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह– अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली।

> • **इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह– अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली**

श्री मोदी ने कहा कि हमारे यहां कहा जाता है– 'जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।' अर्थात् एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक-एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए, 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है तो आइए, हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने-अपने कदम बढ़ाएं। ■

ममता सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 06 फरवरी 2021 को नादिया (पश्चिम बंगाल) के चतिर मठ मैदान से हरी झंडी दिखाकर राज्यव्यापी 'परिवर्तन यात्रा' का शुभारंभ किया। विदित हो कि यह 'परिवर्तन यात्रा' पांच चरणों में राज्य की सभी 294 विधान सभाओं से होकर गुजरेगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल पहुंचने पर श्री नड्डा ने सेन्ट्रल इंस्टीटयूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टीकल्चर में प्राध्यापकों एवं रिसर्चरों से संवाद किया। इसके पश्चात् वे शाहपुर, मालदा में तीन हजार से अधिक किसानों के साथ 'कृषक सुरक्षा सह-भोज' में शामिल हुए। उन्होंने मालदा में एक भव्य रोड शो किया। वे नबद्वीप (नादिया जिला) में श्री श्री गौरंगा जन्मस्थान आश्रम भी गए जहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर पश्चिम बंगाल की शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना की।

पश्चिम बंगाल की पुण्य भूमि को नमन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि विचार का परिवर्तन है। 10 साल पहले मां, माटी, मानुष के नारे के नाम पर ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी लेकिन इन 10 वर्षों में इस नारे की जगह तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टिकरण की राजनीति ने ले ली है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के तृणमूल सरकार में मां को लूटा गया, पश्चिम बंगाल की अस्मिता पर आघात किया गया। न तो माटी की इज्जत की गई और न ही नागरिकों के साथ न्याय ही किया गया। ममता सरकार ने 10 वर्षों में प्रशासन का अपराधीकरण कर दिया और भ्रष्टाचार को संस्थागत बना

दिया।

ममता सरकार पर हमला तेज करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को न केवल आयुष्मान भारत योजना से महरूम रखा बल्कि राज्य के लगभग 70 लाख किसानों तक

• 10 साल पहले मां, माटी, मानुष के नारे के नाम पर ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी लेकिन इन 10 वर्षों में इस नारे की जगह तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टिकरण की राजनीति ने ले ली है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी नहीं पहुंचने दिया। अगर ममता दीदी ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में अड़ंगा न लगाया होता तो आज पश्चिम बंगाल के सभी 70 लाख किसानों को अब तक 14-14 हजार रुपये मिल चुके होते।

तूफ़ान के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए उठाये गए क़दमों को रेखांकित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अम्फान तूफ़ान से राहत के लिए पश्चिम बंगाल को 2700 करोड़ रुपये दिए लेकिन इसमें भी तृणमूल कांग्रेस ने जम कर घोटाला किया। जब हाईकोर्ट ने सीएजी से ऑडिट कराने की बात कही तो ममता दीदी इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसका मतलब स्पष्ट है कि ममता दीदी ईमानदारी के बजाय बेईमानी को प्रश्रय को दे रही हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि अब ममता दीदी को 'जय श्री राम' के नारे से भी दिक्कत होने लगी है। क्या अपनी संस्कृति से और अपने महापुरुषों से जुड़ना गलत है? 'जय श्री राम' पर सवाल उठाना बताता है कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीति भारतीय संस्कृति से ऊपर है और ये अपनी राजनीति के लिए अपने जमीर को भी बेच चुके हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में जो नई हवा चल रही है, वह ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की विदाई करने के लिए आतुर है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उन्होंने परिवर्तन का नारा देते हुए कहा कि अनेक होइछे ममता, परिवर्तन चाहे छे जनता। ■

केरल

राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 फरवरी 2021 को कहा कि केरल में हुए गोल्ड स्कैम में मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता ने विश्व भर में मलयाली लोगों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचायी है। श्री नड्डा ने कहा कि ना सिर्फ केरल बल्कि विश्वभर में बसे मलयाली खुद को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। जांच चल रही है तथा इस केस में और खुलासा होने पर कई मंत्री बेनकाब होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनावों का सवाल है तो मुझे पूरी आशा है कि केरल के लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। मौजूदा सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है तथा केरल के लोगों का अपमान कर रही है। ■

तमिलनाडु

एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 30 जनवरी को कहा कि भाजपा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही गठबंधन में अन्य पार्टियां भी शामिल रहेंगी।

श्री नड्डा ने कहा, "मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा ने फैसला किया है कि आने वाले समय में हम एआईएडीएमके और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।" बता दें कि तमिलनाडु में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर यह चुनाव लड़ेंगी।

श्री नड्डा ने मदुरै में महान स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी मुथुरामलिंगा थेवर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने दौरे के दौरान श्री नड्डा ने ट्वीट कर बताया कि मदुरै में वरिष्ठ समाजिक कार्यकर्ता और प्रख्यात व्यक्तियों से सुखद मुलाकात हुई। सम्मानित लोग विजन और अथक प्रयासों की सराहना करते हैं। ■

पुडुचेरी

'दुनिया में जिसे भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए उन्हें हम कराएंगे मुहैया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 31 जनवरी को पुडुचेरी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब 14 देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वादा किया है कि दुनिया में जिसे भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए हम उन्हें वैक्सीन मुहैया कराएंगे। श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके समर्थन के साथ हम पुडुचेरी में बदलाव की शुरुआत करेंगे। पुडुचेरी में कमल खिलेगा। ■

'आत्मनिर्भर भारत' की बुनियाद का बजट

देश के हर नागरिक की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला बजट

अमित शाह

कोरोना की चुनौती और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आम बजट लाना एक जटिल काम था, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट पेश किया। इस बजट के मूल्यांकन में इसकी मूल भावना को दो बिंदुओं में समझना चाहिए। पहला यह कि महीनों तक लॉकडाउन के कारण ठप आर्थिक गतिविधियों के बावजूद यह बजट चुनौतियों से उबरकर आगे बढ़ने की मजबूत इच्छाशक्ति वाले सशक्त भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरा यह कि बजट में भविष्य के 'आत्मनिर्भर भारत' की आकांक्षा रखने वाले देश की संकल्पशक्ति नजर आती है। देश ने महसूस किया है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्पवान हो तो आपदा को अवसर में बदला जा सकता है।

बजट ने 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' के साथ गरीब, किसान, महिला को दी प्राथमिकता

अनेक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना बजट में जनकल्याण के कार्यों को 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब, किसान, महिला, युवा को प्राथमिकता दी है। कृषि की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिहाज से यह बजट विशेष महत्व रखता है। बजट से स्पष्ट है कि किसानों की उपज लागत से डेढ़ गुने अधिक एमएसपी पर खरीदी जाएगी।

किसानों के हित में काम करने वाली मोदी सरकार

बीते वर्ष में गेहूं एवं दाल और चालू वर्ष में धान की खरीद में वृद्धि यह दिखाती है कि केंद्र में किसानों के हित में काम करने वाली सरकार बैठी है। पहले जो किसान यूरिया के लिए पुलिस की लाठियां खाते थे, आज सम्मान निधि की राशि सीधे उनके खातों में पहुंचती है। सरकार ने कृषि ऋण के लिए बढ़ोतरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, 1000 'ई-नाम' के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं।

मोदीजी के नेतृत्व में कोरोना महामारी के दौरान भारत की कार्यशैली ने विकसित देशों को किया चकित

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में महामारी के दौरान देशव्यापी टेस्टिंग नेटवर्क, पीपीई किट उत्पादन में भारत की कार्यशैली ने विकसित देशों को भी चकित किया। स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए उसे 2.38 लाख करोड़ रुपये किया गया है। बजट में प्रस्तावित 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' से लगभग 75 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। नई लैब-नए संस्थान खुलने से स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव होंगे। बजट में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भारत कोरोना टीके के निर्माण और उत्पादन में अग्रणी बना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मोदी जी दुनिया के तमाम देशो में टीका पहुंचाकर भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहे हैं।

बजट में सबके लिए कुछ न कुछ

बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है। उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ महिलाओं तक मुफ्त रसोई गैस पहुंचाने के बाद अब एक करोड़ अन्य लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बजट में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट का निर्णय सरकार के मानवतावादी नजरिये का प्रतीक है। मत्स्य उद्योग से जुड़े लोगों के हित में पांच नए बंदरगाह बनाने और प्रवासी मजदूरों के डाटा को एकीकृत करने का प्रस्ताव है, जिससे वे 'एक देश-एक राशन कार्ड' का लाभ उठा सकें। मध्यम वर्ग के हित में सस्ते घर के लिए कर्ज

में छूट की अवधि एक साल और बढ़ाई गई है। मोदी जी ने गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, शुद्ध जल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया है, उसे यह बजट सिद्धि तक ले जाने में सहायक होगा।

जन के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध मोदी सरकार, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से दुःख होता है

बीते सात दशकों में अनेक सरकारें आईं, किंतु वैश्विक पटल पर भारत की साख को बढ़ाते हुए युगानुकूल आर्थिक सुधारों के साथ सामान्य जन के कल्याण के प्रति इतनी प्रतिबद्ध सरकार पहले कभी नहीं आई। आज देश आर्थिक महाशक्ति बनने को तैयार है, किंतु मुझे कई बार दुःख होता है कि कुछ विपक्षी दल देशहित के मसलों पर भी नकारात्मक विचारों से राजनीति करते हैं। ऊपर जिन कार्यों का मैंने उल्लेख किया, वे सभी आमजन के जीवन में बेहतर बदलाव लाने वाले हैं। क्या यह सब तब संभव है जब देश आर्थिक रूप से कमजोर हो?

मोदी के नेतृत्व ने देश को समृद्ध करने के लिए आर्थिक सुधारों से गति देने का किया काम

मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को, जिन्होंने देश को समृद्ध करने के अभियान को आर्थिक सुधारों से गति देने का काम किया है। महामारी के बाद रिसेटिंग मोड में चल रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के लिए नए अवसर हैं। इस बजट में इन अवसरों को परिणाम में बदलने की नीतिगत योजना दिखती है। आज देश को आर्थिक विकास में अपनी संपूर्ण ऊर्जा और क्षमता के साथ जुटना होगा। निजी क्षेत्र भी हमारी इसी ऊर्जा का हिस्सा है। मोदी सरकार ने पारदर्शी और सुगम व्यवस्था देकर आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है और आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 1.18 लाख करोड़ रुपये के बजट से राजमार्गों के विस्तार को नई गति मिलेगी।

रेलवे को रिकार्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया

रेलवे को अगले एक दशक की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए रिकार्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसके साथ जलमार्गों, बंदरगाहों के विकास हेतु पूंजी निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिये अनेक कदम उठाए गए हैं। आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह पिछले वर्ष के 4.21 लाख करोड़ से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देते हुए 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा करने से राहत दी

सरकार ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें 31 मार्च 2022 तक टैक्स जमा करने से राहत दी है। अर्थव्यवस्था की धुरी और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले लघु एवं मध्यम उद्योगों की मजबूती के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही बैंकिंग तंत्र में सुधार, ऋण प्राप्ति की सुगमता एवं आर्थिक विवादों के निपटारे के कदम उठाकर आर्थिक उन्नति को सुगम बनाया गया है। इन कदमों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा है। गत तिमाही में यह 24.6 अरब डॉलर तक पहुंचा।

'आत्मनिर्भर भारत' के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट

नए दशक में लाया गया यह पहला बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को पूरा करने की बुनियाद रखने वाला है। बजट देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट है। ■

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चार राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए

भाजपा ने 2021 में देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 2 फरवरी 2021 को चार राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों के नामों की घोषणा की है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को असम का प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को असम का सह-प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी को तमिलनाडु का प्रभारी और डॉ. वीके सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह, केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को केरल का प्रभारी बनाया गया है, जबकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण को सह-प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को पुदुचेरी का प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव चंद्रशेखर को सह-प्रभारी बनाया गया है। ■

मोदी सरकार वंचित वर्गों के हित में हरसंभव कदम उठाएगी: अनुराग ठाकुर

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कमल संदेश के लिए रमाकान्त पाण्डेय के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि मोदी सरकार समावेशी विकास के लिए किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के फायदे के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। यहां हम अपने सुधी पाठकों के लिए साक्षात्कार के प्रमुख अंश प्रकाशित कर रहे हैं:

• वैश्विक महामारी के दौर में पूरे विश्व के सामने अनेक चुनौतियां आयीं। इस बजट के माध्यम से देश किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना करेगा?

दुनिया के सामने यह इतनी बड़ी चुनौती थी कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया के देश असमंजस में थे कि प्राथमिकता क्या हो? कुछ ने अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता माना और लॉकडाउन नहीं किया, उन देशों की हालत आपके सामने हैं। और कुछ देशों ने लॉकडाउन किया लेकिन फिर भी बहुत सारी जान नहीं बचा पाए। लेकिन भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लॉक डाउन भी किया और अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया और जो चुनौतियां थीं उनका सामना करते हुए आज भारत दुनिया भर के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में है।

• भारत में 'मेड इन इंडिया' टीकों का निर्माण कर अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की है, टीकाकरण के लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बजट में 137% की अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। इसका कितना सकारात्मक प्रभाव देश पर पड़ेगा?

हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हर भारतीय की जान को बचाया जाए, अपनी ताकत को बढ़ाया जाए और वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किया जाए। पहले हमारे यहां पीपीई किट एक भी नहीं थी, उनको बनाने के लिए कोशिश किया जाए और आयात न किया जाए। वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग लैब जो पहले केवल एक था आज 2400 से ज्यादा है। आज हम 12 लाख से ज्यादा टेस्ट 1 दिन में कर सकते हैं। तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारी पहली चुनौती थी 'जान है तो जहान है' और दूसरा 'जान भी जहान भी' हमने दोनों पर काम किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीपीई किट आज हम निर्यात कर रहे हैं और कोविड वैक्सीन भारत ने एक नहीं बल्कि दो-दो बना ली है और वह दुनिया के गिने-चुने देशों में शामिल है। और हम आज 100 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन पहुंचा भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मध्यम, लघु, सूक्ष्म कुटीर उद्योग को धन उपलब्ध कराकर और बहुत सारे कदम उठाकर यह प्रयास किया कि उनके धंधे बंद ना हो, रोजगार ना जाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती रहें। तो हमने 3,00,000 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी के 20% अतिरिक्त धनराशि भी दी है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए गए जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला और हमारे उद्योग धंधों को भी लाभ मिला।

• बजट में छह स्तंभ की बात की गई है। इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है, इसका देश को क्या लाभ मिलेगा?

निश्चित तौर पर आज अर्थव्यवस्था को निवेश की जरूरत है, माहौल तभी बनता है जब सरकार निवेश करती है। सरकार ने लगभग 35% का खर्च बढ़ा दिया है सड़कों में 1,18,000 करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए, पानी के जल जीवन मिशन के लिए 50,110 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए वह भी 137% वृद्धि के साथ, मजदूरों के मनरेगा के लिए 73,000 करोड रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 65,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बल देने के लिए 20,000 बसें खरीदने का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब आदमी को अच्छी बसों में सफर करने का लाभ मिले, मेट्रो ट्रेन को दोगुना करने की बात की गई है। तो इन सबसे लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, रोजगार भी मिलेगा और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। तो निश्चित तौर पर यही

एक तरीका है और दुनिया भर के अनुभव देखे जाएं तो यह देखा जाता है कि अगर 500 साल पहले भी कोई आपदा आती थी तब भी राजा-महाराजा खर्च किया करते थे ताकि जनता को पैसा मिले, जनता को रोजगार मिल सके। आज भी सरकार का यही दायित्व बनता है कि सरकार ज्यादा खर्च करें ताकि रोजगार उत्पन्न हो और सरकार को देखकर प्राइवेट सेक्टर में निवेश करें। और आज के समय देखा जाए दोनों को मिलाकर के, एफडीआई कोविड के दौरान भी बहुत आया। हमारी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे लगभग 10 सेक्टर में रोजगार मिलेगा और निवेश भी आएगा। फिर जिस तरह से हमने मेगा टैक्सटाइल पार्क की बात की है तो उसमें भी रोजगार उत्पन्न होगा। तो सरकार का मुख्य लक्ष्य इसी बात पर है कि हम किन किन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। कहां बढ़ोतरी हो सकती है और भारत लीडर बन सकता है।

• आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के अंतर्गत किसानों मजदूरों और वंचित वर्ग के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा?

सरकार वह हर कदम उठाएगी जो समावेशी विकास के लिए किसानों मजदूरों और वंचित वर्ग के लिए लाभदायक हो। इसके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं जिनका क्रियान्वयन लगभग हर मंत्रालय से होगा। एससी-एसटी के लिए हर मंत्रालय में लगभग 5% की वृद्धि की गई है, सभी मंत्रालयों को मिलाकर देखें तो यह काफी अधिक हो जाता है। सभी क्षेत्रों में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई हैं।

कोविड के दौरान समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ दिया गया है जैसे वह होटल जो लघु उद्योग में आते हैं उनको 20% की अतिरिक्त सहायता दी गई। दिवालियापन की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया गया और देश में कोल्ड स्टोरेज की चैन स्थापित करने के लिए बजट में व्यवस्थाएं की गई हैं। आज तो हम पैसा लेकर खर्च करेंगे और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाएंगे। यह ऐसा पारदर्शी बजट है जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है और भारत के भविष्य को भी इस बजट में देखा जा रहा है। वैश्विक महामारी में देश के

• सरकार वह हर कदम उठाएगी जो समावेशी विकास के लिए किसानों मजदूरों और वंचित वर्ग के लिए लाभदायक हो

रूप में भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ध्यान दिया गया है इससे अधिक रोजगार पैदा होंगे।

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा?

अगर आप अंतरराष्ट्रीय संगठनों को देखें तो आईएमएफ ने कहा कि भारत की विकास दर 11.5% रहेगी, आरबीआई ने कहा कि यह 10.5% से ज्यादा रहेगी। तो दुनिया के संगठनों ने भारत के विकास दर को डबल डिजिट में ही रखा है यह अपने आप में अच्छी बात है। क्योंकि हमने जो कदम 'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणाओं के बाद उठाया है चाहे वह पावर सेक्टर के लिए हो, कोल सेक्टर के लिए हो, कृषि की बात हो, रक्षा उत्पादन की बात हो, स्पेस सेक्टर की बात हो या खनन की बात हो तो इन सब से क्या लाभ मिला। 90 के दशक में इतना सुधार नहीं हुआ जितना आपदा के दौरान हुआ। मोदी जी ने आपदा में अवसर ढूंढने का काम देखा और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दी। इसीलिए पिछले 4 महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा है और जनवरी में तो यह लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये हुआ। इसीलिए दुनियाभर के देश कहते हैं कि भारत में V आकार में रिकवरी हुई है इसका मुख्य कारण यही था कि भारत ने कोविड पर जीत दर्ज की। अब तक जितना भी काम किया है अर्थव्यवस्था वापस खड़ा करने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वह बड़े साहसिक थे जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी।

किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में समय लगता है जैसे आपने देखा कि 11वीं अर्थव्यवस्था से छठी अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने मात्र 5 वर्षों का समय लिया। इसी तरह से हमारे प्रयास जारी थे, लेकिन पूरा वर्ष इस वैश्विक आपदा के कारण खराब हो गया। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस आने में समय लगता है, लेकिन हमने जो कदम उठाए उसके कारण तेजी से भरपाई होती देखी गई है। यह अच्छा बजट था इसीलिए शेयर बाजार में पहले दिन 2200 अंकों से ज्यादा बढ़ोतरी हुई और दूसरे दिन 1200 अंक से ज्यादा था और अब बाजार 50,000 अंक से ज्यादा पहुंच गया। यह सब अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से अच्छे कदम उठाने पर माहौल भी ठीक होता है और निवेश भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की दिशा में यह बजट एक मजबूत कदम होगा। ■

देश की सेहत, सूरत और सीरत संवारने का संकल्प

रघुवर दास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, वह देश की सेहत, सूरत और सीरत सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। बजट के केंद्र में स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और रोजगार है। यही सबसे बड़ी आवश्यकता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की गई है, बकायदा योजनाओं का ब्लूप्रिंट पेश किया गया है। इस बजट की खासियत यह है कि यह खर्च और बचत का संतुलन साधता दिख रहा था और वह भी कोरोना के संकट के बावजूद किसी भी वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर। वित्त मंत्री ने देश की सेहत की चिंता करते हुए पिछले बजट की तुलना में स्वास्थ्य का बजट दोगुना कर दिया है। पहली नजर में यह वृद्धि 137 प्रतिशत ही दिखाई देती है, लेकिन यदि पोषण, पेयजल और स्वच्छता पर खर्च होनेवाली राशि को मिला दे तो यह वृद्धि दोगुनी हो जाती है। कोरोना काल में हम सब ने पूरी शिद्दत से महसूस किया कि सेहत के मोर्चे पर हमें अब कुछ खास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में देश की यही चिंता बजट में 2,23,846 करोड़ रुपये के प्रावधान के रूप में अभिव्यक्त हुई है। कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में मास्क, पीपीई किट, फेसशिल्ड, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था जिस तत्परता से की गई, वह अपने आप में एक अन्यतम उद्धारण है।

देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा किए बगैर देश की सूरत बदलने वाली नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा रोजगार देनेवाले ऑटोमोबाइल, रियल इस्टेट और टेक्सटाइल सेक्टर को बजट के माध्यम से प्रोत्साहित तथा गतिशील बनाने का प्रयास किया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सालों पूरानी मांग स्क्रैप पॉलिसी को बजट में मंजूरी मिल गयी है। इसके कारण एक अनुमान के मुताबिक ऑटो सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश आएगा और पचास हजार नई नौकरियां पैदा होंगी। स्टील पर ड्यूटी कम होने का लाभ तो ऑटो कंपनियों को मिलेगा ही, स्क्रैप पॉलिसी के कारण कच्चा माल भी सस्ता हो जाएगा। इससे कारों की कीमतों में 30 प्रतिशत तक कमी हो जाएगी।

बजट में तीन साल में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। इन टेक्सटाइल पार्क को मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए के लिए नायलॉन के धागे पर आयात शुल्क ढाई प्रतिशत घटा दिया गया है। बजट में कपड़ा मंत्रालय को पहले से अधिक रकम तो दी गई है, इसे सेक्टर का आकार बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है टेक्सटाइल उद्योग चल पड़े तो रोजगार बेहतर बेतहाशा बढ़ेंगे।

• बजट में तीन साल में सात मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है। इन टेक्सटाइल पार्क को मैन्युफैक्चरिंग तथा एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए के लिए नायलॉन के धागे पर आयात शुल्क ढाई प्रतिशत घटा दिया गया है

वित्त मंत्री ने अपने बजट में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। इससे देश की सीरत बदलेगी तथा वोकल फॉर लोकल की आवाज और तेज होगी। इसके लिए बजट में हर उस सामान का आयात महंगा कर दिया गया है जिसे हम स्वयं बना सकते हैं या बनाते हैं। बजट में कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी में बरसों बाद बदलाव किया गया है, जिसके कारण कुछ वस्तुएं जैसे फ्रिज, एसी, मोबाइल, मोबाइल चार्जर आदि के महंगे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा निर्णय आवश्यक था। उदाहरण के तौर पर देखें तो इथाइल अल्कोहल का आयात महंगा कर दिया गया है। इससे एथनॉल

बनता है, जिसका इस्तेमाल क्लीन फ्यूल बनाने में किया जाता है। लेकिन जब हम स्वयं गन्ना, मक्का और धान के अवशेषों से एथनॉल बना सकते हैं, बना भी रहे हैं। तब इसके महंगे आयात के बदले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा बढ़ाने पर जोर क्यों न दिया जाए। इसी प्रकार घरेलू तेल कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रूड पॉम आयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट में स्टील तथा आयरन स्क्रैप तो सस्ते किया गया है, लेकिन स्क्रू, नट, बोल्ट का आयात महंगा कर दिया गया है। यानी कच्चा माल तो हम बाहर से सस्ती दर पर मंगा सकते हैं, लेकिन तैयार माल मंगाना महंगा पड़ेगा। उद्देश्य यही है कि सस्ते कच्चे माल से जरूरत की चीजें हम खुद बनाएं, बेचें और बाहर भी भेजें।

किसान आंदोलन और कृषि उपज खरीदने वाली मंडियों कीक खात्मे की अफवाहों के बीच वित्त मंत्री ने ग्रामीण और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। यह फंड एपीएमसी मंडियों के लिए भी है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि कृषि ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ तक किया जा सकता है। इसी प्रकार 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं और सड़क निर्माण के लिए 1.18 करोड़ रुपए यानी कृषि, रेलवे, सड़क पर खर्च बढ़ेगा तो रोजगार के नये द्वार निश्चित रूप से खुलेंगे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से एक करोड़ नये कनेक्शन देने का संकल्प बजट में व्यक्त किया गया है। जहां तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, पहले यह राशि 20 करोड़ थी। यह राशि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी छात्रों की पढ़ाई पर खर्च होगी। पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी छात्रों के लिए विद्यालयों को 48 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीपीपी मॉडल की मदद से 100 नये सैनिक और 15 हजार आदर्श स्कूल बनाने के साथ ही बजट में एससी छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है।

सरकार ने अपने बजटीय प्रावधानों और प्रयासों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण पर भी ध्यान दिया है। पहली बार किसी सरकार ने इस मद में खर्च का प्रावधान किया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मॉनिटरिंग सेंटर तो बनेंगे ही, ऊर्जा निगम और नवीनकरणीय ऊर्जा विकास में अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष विभाग का बजट 470 करोड़ बढ़ाकर सरकार ने यह संदेश-संकेत दे दिया है कि हम अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई इबारतें आगे भी लिखते रहेंगे। सरकार ने विश्वस्तरीय संस्थानों को अपने यहां स्थापित करने के मकसद से इस मद में बजट 3 गुना बढ़ा दिया है यानी सरकार हर मोर्चे पर सतर्कता के साथ काम करने की तैयारी दिखा रही है। सरकार ने बजट प्रावधानों के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास का जो खाका खींचा, उसके लिए फंड को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने अपने भाषण में ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन और डेवलपमेंट फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट के माध्यम से फंड जुटाया जाएगा। यानी सरकार उन सरकारी कंपनियों, संस्थानों को विनिवेश के हवाले करेगी जो सफेद हाथी बन गए हैं। सरकार बाजार से उधार लेकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाएगी, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग की सभी परियोजनाएं पूरी की जाएंगी।

• उज्ज्वला योजना के माध्यम से एक करोड़ नये कनेक्शन देने का संकल्प बजट में व्यक्त किया गया है। जहां तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, 750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, पहले यह राशि 20 करोड़ थी

कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना, लेकिन जिन्हें करना है वे भला कहने वालों की परवाह क्यों करेंगे। जिन लोगों ने विनिवेश के दरवाजे खोलें, खुली अर्थव्यवस्था के श्रीगणेश के लिए वाहवाही लूटी आज वे ही अगर फंड जुटाने के लिए सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाएं, तो सिर्फ उन पर हंसा ही जा सकता है। महामारी के हमले झेल रही किसी भी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बिना टैक्स बढ़ाये जो सर्वोत्तम करणीय था, वित्त मंत्री ने किया है। इसके लिए उन्हें बधाई और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को साहस और समझ-बूझ से सरल बना देते हैं।

आइये, हम सब मिलकर एक ऐसे मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें, जो बेरोजगारी एवं अशिक्षा के अभिशाप से मुक्त हो तथा जहां कोई क्षेत्र विकास से अछूता न रहे। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं)

'कृषक सुरक्षा सह-भोज' कार्यक्रम संपन्न

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 06 फरवरी 2021 को अपने पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान मालदा के शाहपुर में लगभग तीन हजार किसानों के साथ पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रम 'कृषक सुरक्षा सह-भोज' में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण किसानों को संबोधित किया। शाहपुर, मालदा में श्री नड्डा तीन हजार से अधिक किसानों के साथ 'कृषक सुरक्षा सह-भोज' में शामिल हुए। ज्ञात हो कि 09 जनवरी 2020 को भाजपा अध्यक्ष ने बर्धमान से 'कृषक सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता राज्य के 40,000 ग्राम सभाओं में ग्राम सभाएं कर 'एक मुट्ठी चावल' का दान लेते हुए किसानों के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रण ले रहे हैं। हजारों किसानों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भोजन किया और किसानों के कल्याण के लिए भाजापा की प्रतिबद्धता जताई। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, लोक सभा सांसद सुश्री देबोश्री चौधरी, श्री महादेव सरकार, श्री अरविंद मेनन और सांसद श्री खोगेन मुर्मू सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान उपस्थित थे और उनका जोश देखते ही बनता था।

किसानों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कृषक सुरक्षा अभियान के तहत अब तक पश्चिम बंगाल के लगभग 35 लाख किसान जुड़ चुके हैं। अब तक 35 हजार गांव तक हमारा यह अभियान पहुंच चुका है, लगभग 33 हजार ग्राम सभाएं हो चुकी हैं। जल्द ही हम राज्य के 40,000 गांव तक पहुंचेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं लेकिन ममता दीदी ने अपनी जिद और अपने अहंकार में किसान हितैषी इस योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जिसके कारण यहां के लगभग 70 लाख किसान इस योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। ■

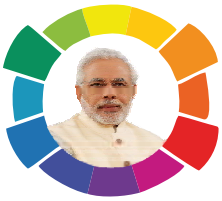

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

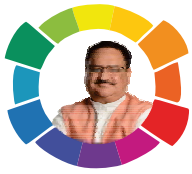

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस संवाद को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरी चौरा, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में 'चौरी चौरा' शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

असम में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आधारशिला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

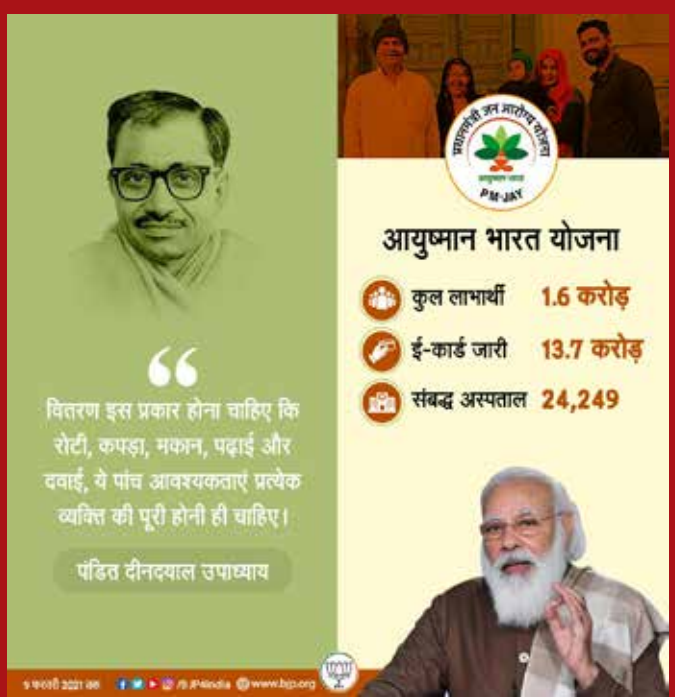

छायाकार: अजय कुमार सिंह